बीएचयू और क्योटो यूनिवर्सिटी में समझौता

दोनों विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

वाराणसी। बीएचयू और क्योटो यूनिवर्सिटी अब पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मिलकर शोध करेंगे। शुक्रवार को दोनों विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के बीच एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर किया गया। बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय में क्योटो के ग्रेजुएट स्कूल आफ ग्लोबल एनवायरमेंटल स्टडीज के डीन प्रो. शिजीओ फूजी और बीएचयू के रजिस्ट्रार डॉ. केपी उपाध्याय ने इस शोध एवं शैक्षणिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर क्योटो यूनिवर्सिटी के शोध छात्र रॉनित चटर्जी और बीएचयू के शोध छात्र प्रमित वर्मा द्वारा बनारस के 90 वार्डों पर तैयार की गई शोध रिपोर्ट का भी विमोचन किया गया।

क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रो. राजीब शॉ ने बताया कि क्योटो यूनिवर्सिटी का दुनिया के करीब 100 शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता है लेकिन भारत के किसी विश्वविद्यालय के साथ यह पहला समझौता है। बीएचयू के पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान (आईईएसडी) और क्योटो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल स्टडीज के बीच जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर संयुक्त रूप कार्य करने की सहमति हुई है। आईईएसडी बीएचयू के निर्देशक प्रो. एएस रघुवंशी ने बताया कि ये समझौता बेहद खास है क्योंकि यह सीधे काशी के विकास से जुड़ा है। इसके तहत एक अप्रैल से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। चार महीने बाद दोनों यूनिवर्सिटी के बीच एक और समझौता होगा, जिसमें बीएचयू के अन्य संकाय और विभागों को भी शामिल किया जाएगा। इस मौके पर बीएचयू रेक्टर प्रो. कमलशील, मेयर रामगोपाल मोहले, काउंसलर मासे हीरोयूकी, जापानी एंबेसी के मंत्री अकियो इसो माता आदि रहे।

महापौर को रिपोर्ट सौंपते क्योटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, छात्र व केंद्र सरकार के अधिकारी।

इन मुद्दों पर बनी सहमति

- दोनों विश्वविद्यालयों के छात्र एक-दूसरे विश्वविद्यालयों में आएंगे-जाएंगे
- आपस में वैज्ञानिक उपकरणों का आदान-प्रदान होगा,
- शोध और कांफ्रेंस में भी दोनों ही जगह के अध्यापक और शोध छात्र हिस्सा लेंगे
- ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा,
- क्योटो की शोध छात्रा और टाउन प्लानर नेहा साहू बीएचयू में रोड, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सैनिटेशन और स्वास्थ्य पर शोध करेंगी,
- बीएचयू के प्रमित वर्मा पहले छात्र होंगे जो शोध के लिए क्योटो विश्वविद्यालय जाएंगे

हर जोन में बनाया जाए कम्यूनिटी लर्निंग सेंटर

वाराणसी। आपदा प्रबंधन में शहर का आदमपुर जोन तैयार है, जबकि दशाश्वमेध जोन सबसे पिछड़ा हुआ है। यह तथ्य क्योटो के शोध छात्र रॉनित चटर्जी और बीएचयू के शोध छात्र प्रमित वर्मा द्वारा बनारस शहर के पांचों जोनों और 90 वार्डों में किए गए शोध में सामने आया है। शहर के हर जोन में कम्यूनिटी लर्निंग सेंटर बनाने के सुझाव भी दिए गए हैं। शहर के 90 वार्डों के पर्यावरण और आपदा प्रबंधन पर क्योटो विश्वविद्यालय के प्रो. राजीब शॉ की देखरेख में तैयार की गई यह रिपोर्ट 'क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेसिलिएंस आफ वाराणसी' शुक्रवार को महापौर रामगोपाल मोहले को सौंपी गई। महापौर ने कहा कि रिपोर्ट के तथ्यों को वे अपने शहर की बेहतरी के लिए उपयोग करेंगे। शोध की रिपोर्ट को साझा करते हुए प्रो. राजीब शॉ ने बताया कि भेलूपुर और ट्रांस वरुणा जोन में अपशिष्ट प्रबंधन की ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

काशी की तरह और शहर होंगे विकसित

वाराणसी। क्योटो से हुए समझौते से अगर काशी को लाभ होता है और यहां की बुनियादी सुविधाओं में सुधार आता है तो क्योटो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जापान सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर जापान भारत के अन्य शहरों के विकास में भी सहयोग करेगा। शुक्रवार को नगर निगम में महापौर रामगोपाल मोहले से मुलाकात के दौरान यह संकेत क्योटो विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने दिए। क्योटो विश्वविद्यालय के ग्लोबल इन्वायरमेंट स्टडीज के डीन प्रो. सीजिओ फुजी बनारस में हुए स्वागत से अभिभूत दिखे। नगर निगम में महापौर से उन्होंने कहा कि काशी से उनकी भारत यात्रा की शुरुआत हुई है, जल्द ही वे देश के कई अन्य हिस्सों की यात्रा करेंगे। बताया कि वे सेनिटेशन और सिटी मॉर्डनाइजेशन के एक्सपर्ट हैं और चाहते हैं कि उनकी इस खूबी का भारत में उपयोग हो। इससे पहले शुक्रवार की सुबह जापानी दल ने राजघाट से अस्सी तक नौकायन कर सुबह-ए-बनारस देखा। इस दौरान गंगा में प्रदूषण और घाटों पर गंदगी देख सभी ने दुख जताया। दोपहर बाद जापानी दल ने भगवानपुर एसटीपी और करसड़ा स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण किया।

...तो हम इसीलिए जापान से पीछे हैं

महापौर से मिलने के लिए जापानी प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार की सुबह 8:50 बजे नगर निगम पहुंच गया था लेकिन वहां सन्नाटा पसरा था। महज दो-चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही मौजूद थे। 25 मिनट बाद 9:15 बजे नगर आयुक्त आए जबकि पूरे एक घंटे बाद 9:50 बजे महापौर मोहले पहुंचे। हालांकि आते ही उन्होंने खेद प्रकट किया लेकिन मौके पर मौजूद रहे लोगों के मुंह से यही निकला कि हम भारतीयों को समय की कद्र नहीं इसीलिए हम जापान से काफी पीछे हैं।

साल के अंत तक दिखने लगेगा असर

वाराणसी। काशी के विकास के लिए क्योटो से हुए समझौते का असर इस साल के अंत तक दिखने लगेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काशी के विकास के लिए किए गए समझौतों को क्रियान्वित कराने के लिए विदेश मंत्रालय पूरी तत्परता से कदम उठा रहा है। नगर निगम में शुक्रवार को महापौर राम गोपाल मोहले से मुलाकात के दौरान यह जानकारी विदेश मंत्रालय की डायरेक्टर (टेक्निकल को-आपरेशन) डॉ. देवयानी खोब्रागड़े ने दी। डॉ. देवयानी ने कहा कि हम यहां इसलिए आए हैं ताकि इस साल के अंत तक काशी में क्योटो से हुए समझौते का असर सफाई, पेयजल आपूर्ति, यातायात सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार के तौर पर दिखने लगे। इसके लिए विदेश मंत्रालय हरसंभव मदद देगा। डॉ. देवयानी ने महापौर को बताया कि ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों से छूती हैं, उनके लिए विदेश मंत्रालय में अलग से विभाग बनाया जा रहा है। इसका उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को बहुत लाभ मिलेगा। चूंकि यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। इसलिए यहां के विकास में मदद के इच्छुक अन्य देशों को भी भागीदार बनाने का प्रयास किया जाएगा।

विदेश मंत्रालय की डायरेक्टर डॉ. देवयानी ने दी जानकारी